बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014
संख्या– FC/130/2020- 512

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक– 10/06/2022

विषय– श्री अजय कुमार द्वारा सुपौल जिलान्तर्गत श्रीपुर ग्राम के खाता संख्या–60, खेसरा संख्या–3719 में NH-57 पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0285 है. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/49280/2020/4557, दिनांक 26.02.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 31.05.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है–

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, राँची का पत्र दिनांक 26.02.2021 में निहित कंडिका	अनुपालन
A:	**Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the Stae Forest Department.**	
1	The User agency shall transfer the const of raising and maintain the compensatory afforestation (100 trees plantation and maintenance for 10 year) at the current wage rate in consultation with state forest department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा हरितावरण को बनाये रखने के लिए 100 वृक्षों के रोपण तथा उनके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु रू० 7,55,315.00 (रू० सात लाख पचपन हजार तीन सौ पंद्रह) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No. 150621994928093 4, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, New Delhi, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 22.10.2021 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. BKIDH21295944226 है । उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

Email-apccfcampa.bih@gmail.com;
मो० 8986153123

2	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.0285 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.0105 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रू० 6.26 लाख प्रति हे० की दर से कुल रू० 17,841/- (सतरह हजार आठ सौ एकतालीस रूपये) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No. 1506219949280934, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, New Delhi, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 22.10.2021 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. BKIDH21295 944226 है । उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
3	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred deposited to CAMPA fund only through e-protal	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी प्रकार की राशि e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 22.10.2021 को राशि जमा करा दी गई है (बैंक e-challan RTGS/ NEFT की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न)।
4	The FRA, 2006 certificate as per ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of final approval. The comlete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the	जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न भेजा जा रहा है।
5	18 plants should be translocated by the User agency at their own cost with using modern techology uder the strict supervision of the concerned DFO.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
6	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
7	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website पर अपलोड कर दिया गया।
B:	**Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the Usr Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage – II approval:**	
1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2	The state forest department shall plant 100 trees to maintain the green cover at the project cost. Plantation site for the purpose	100 पौधों के रोपण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा जमा करा दी गयी है। अंतिम स्वीकृति के उपरांत उक्त कार्यों को वन विभाग के द्वारा किया जायेगा।
3	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होती है, तो उसका भुगतान करेंगे।

4	The approach road to petrol pump/ fuel station should be as per	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
a	Fuel station should generally be part of rest area complex	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
b	Suitable signs and markings showing the location of the fuel	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
c	Entire Periphery of the retail outlet should be lined up with	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
d	Suitable plantations should be raised by the user agency along the approach road, separator	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
5	Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall in consultation with SFD undertake approvprivate	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
6	The User Agency shall ensure that the loaboures and staff engaged in construction acitivity do not damage the nearby forest flora and fauna.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
7	The lay out plan of the proposal shall not be changed without	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
8 (a)	The forest land shall not be used for any purpose other than	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(b)	The period of diversion under this approval shall be	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(c)	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
9	Any other conditions that the Ministry of Environment, ...	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage– I) में अधिरोपित सभी शर्त्तों का अनुपालन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 0.0285 हे० सुरक्षित वन घोषित पथ किनारे की भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage – II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। **प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुशंसा प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),

–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

Email-apccfcampa.bih@gmail.com;

मो० 8986153123

ज्ञापांक– FC/130/2020- 512 दिनांक– 10/06/2022

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ /वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल वन प्रमंडल, सुपौल एवं श्री अजय कुमार, पिता–श्री मानिक चन्द यादव, ग्राम+पोस्ट–हुल्लास, थाना–राघोपुर, जिला–सुपौल, पिन–852111 को सूचना हेतु प्रेषित।

9/6/22

(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

Email-apccfcampa.bih@gmail.com;

मो० 8986153123

Proforma

1	Name of Regional Office	Eastern Region, Ranchi
2	State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates	Bihar/Supaul/ Supaul Forest Division, Supaul.
3	Name of User Agency nature of proposal	Shri Ajay Kumar /IOCL Retail Outlet
4	Extent of forest area involved	0.0285 Ha.
5	Whether Original, or extension	Original
6	If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	-NA-
7	Date of 1st stage Clearance	26.02.2021
8	**Extent of CAMPA charges head wise viz.**	
	a.Compensatory Afforestation	7,55,315.00
	b. Additional CA	-NA-
	C. Penal CA	-NA-
	d. Catchment Area Treatment	-NA-
	e. Wildlife Management Plan	-NA-
	f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas	-NA-
	g. Net present Value	17,841.00
	h. Any other charges/Levies (Pl Specify)	-NA-
9	Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph	
10	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance	As above.
11	Bank in which deposited, with date of deposition.	All above e-challan sent to Union Bank of India, New Delhi on dt. dt. 22.10.2021
12	Any other remarks	

S.No	MODE Remtt.	UTR No. & Date	Amount	Head
1	e-challan	BKIDH21295944226	17,841/-	NPV
2		dt. 22.10.2021	7,55,315/-	CA
		Total-	**7,73,156/-**	

(Arvinder Singh)
Signature of APCCF (CAMPA)-
cum-Nodal Officer (FC), Bihar.

Email-apccfcampa.bih@gmail.com;

मो० 8986153123

प्राप्ति संख्या 593
दिनांक 03/06/2022

45

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक– 31/05/2022

विषय– श्री अजय कुमार द्वारा सुपौल जिलान्तर्गत श्रीपुर ग्राम के खाता संख्या–60, खेसरा संख्या–3719 में NH-57 पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0285 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग– आपका पत्रांक 950, दिनांक 21.10.2021,

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Others/49280/2020/4557, दिनांक 26.02.2021 द्वारा दो भागों में (A में 1–7 शर्त एवं B में 1–9 शर्त) सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ–

भाग–A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the Stae Forest Department.

1. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रू. 7,55,315.00 को मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506219949280934, Union Bank of India, New Delhi में फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 22.10.2021 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- BKIDH21295944226 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।

2. NPV के मद में मेरे द्वारा द्वारा 0.0105 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रू० 6.26 लाख प्रति हे० की दर से कुल रू० 17,841/– को बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506219949280934, Union Bank of India, New Delhi में फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 22.10.2021 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- BKIDH21295944226 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।

3. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर Union Bank of India, New Delhi के खाता में दिनांक 22.10.2021 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

4. जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण–पत्र पूर्व में विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है।

5. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

6. मेरे द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

7. मेरे द्वारा सभी शर्त्तों का Compliance report, Ministry ds Website-http://parivesh.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है।

(५५)

भाग–B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the Usr Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage – II approval:

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्त्तन नहीं करूगा।
2. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
4. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

a. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

b. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

c. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

d. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

5. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
6. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

8. (a) इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

(b) इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

(c) इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

9. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

साथ ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं भारतीय राष्ट्रीय राज्यमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूँ।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्त्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०–यथोक्त

विश्वासभाजन,

Ajay Kumar

अजय कुमार,
पिता–श्री मानिक चन्द यादव,
ग्राम+पोस्ट–हुल्लास, थाना–राघोपुर,
जिला–सुपौल,
पिन–852111

सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)
क्षेत्रीय कार्यालय - पटना
क्लासिकोन शिवमित्रा अपार्टमेन्ट, ब्लॉक-बी, प्रथम तल, विवेकानन्द मार्ग, बोरिंग रोड, पटना - 800 013 (बिहार)
Regional Office - Patna
Classicon Shivmitra Apartment, Block-B, 1st Floor, Vivekanand Marg, Boring Road, Patna-800 013 (Bihar)
फोन / Ph.: 0612-2570898 | फैक्स / Fax: 0612-2570895 | Email : ropatna@nhai.org

43

NHAI/RO-PAT/PIU-Darbhanga/Shripur/Ro-NOC/1095 **Date:- 18.05.2022**

To,

The Project Director
PIU-Darbhanga
National Highways Authority of India

Sub: - Application for the Permission for construction and use of Approaches/ Access road for New retail outlet of M/s IOCL on NH-27 (Old NH-57) at Chainage 179.881(RHS), Khata No. 60, Khesra no./ Plot no. 3719, Mauza-Shripur, Thana- Pratapganj,Dist:- Supaul in state of Bihar. **Reg Provisional NOC**

Ref:-(i) PD, PIU- Darbhanga letter no. 39011/01/2006/PD/PIU/Darbhanga/152 dated 14.03.2022
(ii) This office letter no. 163 dated 19.01.2022

Please refer to this office letter u/r(ii) granting in-principle approval and your letter u/r(i) informing that the fee has been deposited through Bharat Kosh transaction reference no. 2401220009237 dated 24.01.2022 for **Rs. 20,000/-** and transaction reference no. 2401220008610 dated 24.01.2022 for **Rs. 2,75,625/-** as license fee and bank Guarantee for **Rs. 2,50,000/-** having BG No. 4496IPEBG220002 dated 02.02.2022 and requesting to issue provisional NOC for the subject proposal.

2. In view of above, the provisional NOC is hereby granted subject to the following conditions:

(i) The licensee shall, within one year from date of receipt of the permission, but without interfering in any way with the highway traffic, complete the construction of the approach road (including deceleration/acceleration lanes) and shall make provision for drainage, signs and marking at his own cost and to the full satisfaction of the PD, PIU-Darbhanga according to the approved drawings and specification. On completion of construction in accordance with checklist and conforming to the approvals, a completion certificate would be issued by PD, PIU- Darbhanga after satisfying himself that it has been completed as per the approved drawings and specifications. A copy of the necessary completion certificate issued to the Oil Company may also be furnished to this office. In case, the construction is not done in one year, the provisional approval shall be deemed to be cancelled, unless renewed by the Highway Administration.

(ii) The applicant should adhere to the undertakings given by them in compliance to Para 7 to 10 of Annexure-I to Appendix of Ministry's letter No. RW-NH-33032/01/2017-S&R(R) dated-26.06.2020 in the construction of approach road. Any discrepancy would lead to violation of the Ministry's guidelines and the approval extended shall stand cancelled.

(iii) It may also be noted that as per para-11 (ii) & (iii) of Appendix-1 of Ministry's guidelines mentioned above that Retail Outlet is supposed to have free drinking water and toilet facilities as per the policy of Ministry of Petroleum and Natural Gas. It shall also be ensured that Retail Outlet is provided with such facilities and this would be accessible to public round the clock. To inform the public about this, a display board showing location of such facilities be installed before entry to the Retail Outlet. The Oil Company should ensure that this will be implemented prior to energizing the new Retail Outlet. This may be confirmed along with the completion report.

(iv) PD, PIU-Darbhanga should examine the safety conditions at site consequent to construction of approaches. Compliance to the approved drawings and other conditions are to be ensured by the PD, PIU-Darbhanga.

(v) The concerned Oil Company would be allowed to energize the fuel station only after the final approval by Highway Administration. Oil Company should ensure that petrol pump should not be energized before issuance of Completion certificate by PD, PIU-Darbhanga and final NOC from this office.

(vi) Proposal for final approval shall be submitted to this office only after completion of access road in all aspects.

3. Two sets of duly approved drawings are enclosed with the provisional NOC however Licence Deed shall be signed after grant of the final approval from this office.

Yours faithfully,

Encl.:-As above.

(Bibhuti Bhushan Kumar)
Manager(Tech)

Copy to:- (i) Regional Officer, MoRTH, Patna for kind information.
(ii) M/s IOCL for kind information

BIHAR STATE POLLUTION CONTROL BOARD

Parivesh Bhawan, Industrial Area, Patliputra, Patna – 800 010
EPABX - 0612-2261250/2262265, Fax - 0612-2261050
E-mail-bspcb@yahoo.com, Website - http://bspcb.bih.nic.in

(39)

Ref. No. 1901 Patna, dated:- 01.11.2021

'CONSENT-TO-ESTABLISH' (NOC)
UNDER SECTIONS 25/26 OF THE WATER (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1974 AND 21 OF THE AIR (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1981

Reference Online Application ID- **5333932**, dated **29-10-2021** of **M/s HSD Retail Outlet Dealership** of IOCL, Proprietor- Sri Ajay Kumar, resident of At+P.o-Hulash, Ps.-Raghopur, Dist. – Supual-852111 for establishment of Petrol Pump/ Retail Outlet of **Indian Oil Corporation Limited** at Khata no.-60, Khesra no.-3719, Mauza – Shripur, At+Po.-Shripur, Ps.-Pratapganj, Dist.–Supaul with a capital Investment of Rs 51.0 Lacs approx. The storage capacity of the retail outlet will be **80 Kilo Liters/Day of MS/ HSD** and **DG Set of 65 KVA.**

AFTER CONSIDERING:

(i) The facts stated in their application;
(ii) Letter of Intent issued by Indian Oil Corporation Limited letter, date: 18-03-2020.
(iii) Bihar State Pollution Control Board's Notification No. 26 dated 08.11.2003 and notification no-07, dated 27-06-2011;
(iv) Provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 : and
(v) Affidavit dated 29-10-2021 regarding distance of different land marks.

NOC IN FAVOUR OF THE PROPONENT AT THE SAID SITE IS HEREBY ACCORDED SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS:

General Conditions:

1. The proponent shall obtain 'Consent-to-Operate' under sections 25 & 26 of the Water Act,1974 and 21 of the Air Act, 1981 from the Board;
2. Sludge shall be collected, stored and disposed as per Rules 8 of Hazardous Waste (Management and Transboundary) Rules, 2016 and amendments thereof and records shall be maintained.
3. The effluent (domestic or trade) and emission, if any, shall conform to the standard as prescribed by the Board;
4. The diesel generator sets shall be provided with integral acoustic enclosure to meet the prescribed norms w.r.t noise as per the Gazette Notification dated of the Ministry of Environment & Forests, Government of India 12-07-2004. The acoustic enclosure/ acoustic treatment of room should be designed for minimum 25 dB (A) Insertion Loss or for meeting the ambient noise standards, whichever is on the higher. The measurement for Insertion Loss may be done at different points at 0.5 meter from the acoustic enclosure/room and then averaged. The Diesel Generator Sets should also be provided with proper exhausts muffler with Insertion Loss of minimum 25 dB (A).
5. The stack height for the Diesel Generator Sets shall be as below:
   Height of Stack (in Meters) = Height of Building + 0.2√(KVA of DG.Set).
6. The occupier shall ensure that the noise from the operations in the unit does not exceed the prescribed ambient noise standards for the industrial area i.e. 75 dB (A) Leq during the day time and 70 dB (A) Leq during the night. The day time is reckoned in between 6 am and 9 pm the night time is reckoned between 9 pm and 6 am.

7. The unit shall submit approved On Site & Off Site Management Plan before operation.
8. The unit shall provide fire fighting arrangement as per Rule of Fire Fighting Department.
9. The unit shall obtain explosive license from the competent authority.
10. The unit shall have a display board near the site stating name of unit/industry with address/name of proprietor with address and ref memo no and date of consent with its validity period granted by the Board.
11. All workers engaged at retail outlets will be covered under ESI. Oil Marketing Company (OMC) dealers shall implement the personal protective equipment (PPE) as per labour laws.
12. IEC (Information Education Communication) activities should be organized by OMC dealers for workers at regular Intervals in order to sensitize them about harmful impacts of VOC emissions.
13. PESO shall conduct audit of tanks and fuel equipment including pipes, overfill protection equipment and alarm system on annual basis and maintain records.
14. The petrol pumps/ Retail Outlets shall not be located within a radial distance of 50 meters (from fill point/ dispensing units(DU)/ vent pipe whichever is nearest) from schools, hospitals (10 beds and above) and residential areas designated as per local laws. No high tension line shall pass over the retail outlet.

Specific Conditions:

1. Petrol pumps located in areas with high groundwater table i.e. Ground water levels less than 04 meters shall have secondary containment by way of double walled tanks or concrete protection walls so as to minimize groundwater and soil contamination. It shall be the responsibility of OMC to properly get measured groundwater level at the site of proposed petrol pump and ensure implementation of these adequate protection measures for such sites. Details of measures taken by OMC shall be placed in public domain and in case of contradictory view; view of State/ Central Ground Water Board/ Authority will prevail.
2. Retail outlets shall have underground tanks/ above ground tank and its ancillary components such as pipes, flexible connectors, pumps, fittings etc. protected from leaks due to corrosion by adopting materials (HDPE/ Mild Steel etc.) with required protective coating, as applicable, duly approved by PESO.
3. They shall report any major leakage/ spillage of Petrol, Diesel, Lube Oil (more than 1 barrel-165 liters) to this Board, PESO and District Administration under intimation to CPCB within 24 hours of occurrence.
4. Operation of concerned Underground Storage Tank (UST) and its ancillary components shall be stopped immediately and not be resumed till corrective measures to contain and stop leakage/ spillages are implemented to the satisfaction of PESO and this Board.
5. OMCs will be held liable for Environmental Compensation (imposed by this Board) and assessment of environmental damage (depending on extent of contamination in soil and ground water) and site remediation. Consultant/ Expert agency appointed by OMCs for damage assessment and site remediation shall have minimum national/ international experience of 5 years in this field. Various approved methods shall be considered for cleaning underground contaminants
6. The unit shall have Auto Cut off Nozzles which shuts dispensation of fuel if its level in customer fuel tank reaches full capacity.
7. Breakaways to be installed for all the hoses of dispensing units to reduce spillage in the event of customer vehicles moves away with nozzle still in the fueling position.
8. Single/ double plane swivel with breakaway coupling shall be installed for all the dispensing units for better positioning of nozzle while refueling so that it does not fall off accidently.
9. In pressurized dispensation, the DU shall be installed with shear valves to cut the fuel flow from pipe line immediately upon accidental knocking of dispensing units from its position.
10. In pressurized system, all Submersible Turbine Pumps (STPs) are to be installed with line leak detectors and in the event of pipeline leaks STPs shall stop pumping fuel from underground tanks.
11. Emergency stop button switch shall be provided on the Multi-Product Dispenser (MPD) to stop

the dispensation in case of emergency.

12. Automation system shall be installed at all new retail outlets to alert in case of tank leak by way of auto gauging system approved by PESO.
13. The Retail Outlet shall provide overfill alarm through automation.
14. Measures for spill containment in fill point chambers and forecourt area shall be implemented as prescribed by PESO.
15. The retail outlets will have automation system installed which will provide reports on volume balance after every day operation and records shall be maintained.
16. Manual gauging shall be done once in a month and compare the same with Automatic Tank Gauging for accuracy.
17. Daily MS and HSD loss shall not exceed MoPNG prescribed limits. In case of leakage beyond such limits, matter shall be got analyzed by OMCs and further action shall be taken for ascertaining the reasons of losses. In case of leakage resulting in soil/ groundwater contamination:
    a. The unit and the concerned OMC shall report to this Board, PESO and District Administration under intimation to CPCB within 24 hours of occurrence. Operation *of* such UST and its ancillary components shall be stopped immediately
    b. Fuel shall be removed immediately from UST to prevent further release to environment. Measures to prevent explosion due to vapors released due to leakage as recommended by PESO shall be implemented immediately.
    c. OMCs will be held liable of Environmental Compensation (imposed by SPCBs/PCCs) and assessment of environmental damage (depending on extent of contamination in soil and groundwater) and site remediation. Consultant and site remediation shall have minimum national/ international experience of 05 years in this field. Various approved methods shall be considered for cleaning underground contaminants.
    d. Operation of Underground tank and its ancillary components shall not be resumed till corrective measures to contain and stop leakages are implemented to the satisfaction of PESO and concerned SPCB.
18. All underground tanks and pipelines shall be subjected to test for leaks every 7 years.
19. The *retail* outlet set up with sale potential of 300KL MS per month and setting up in cities with population more than 1 lakh will be provided with Vapour Recovery System (VRS). VRS should be functional by the time of sale of MS touch 300 KL. In case of failure of installation of VRS, Environment Compensation will be levied by this Board equivalent to the cost of VRS and this will further increase proportionate to the period of non- compliance.
20. The retail outlet set up in cities having population more than 10 lakh and having sale potential of 100 KL MS per month will be provided with VRS. VRS should be installed within a period 03 months from the day of sale of MS touch 100 KL. In case of failure of installation of VRS, Environment Compensation will be levied by this Board equivalent to the cost of VRS and this will further increase proportionate to the period of non-compliance.
21. In case of Stage-II VRS, nozzle shall be provided with flexible cover flap or other alternative system for proper covering of filling tank and therefore proper recovery of vapors.
22. OMCs are responsible for maintaining installed VRS. They have to maintain periodic inspections for A/L regulator as prescribed by Legal Metrology. Proper record shall be maintained.
23. Working of dispenser unit shall be interlinked with VRS functioning. Online system shall be developed within 06 months to monitor status of operation of VRS. In case of non-operation of VRS, the same shall be automatically reported to concern OMC. VRS shall be brought into operation immediately within 24 hrs and in any case within 72 hrs falling which sale of MS shall be stopped from the fuelling station. Proper records of operation of VRS shall be maintained.
24. Work zone monitoring for Total VOC and Benzene shall be conducted by OMCs for petrol pumps selling more than 300 KL/ month and more than 10 lakh population (in first phase) by E(P) Act,1986 approved labs once in a year to check compliance with OSHA norms (Time-Weighted Average) and report shall be submitted to this Board. In addition, pilot study shall be conducted by OMCs through expert institutions for online monitoring of VOCs.
25. Ground water and soil quality monitoring within petrol pump selling more than 300 KL/ month and more than 10 lakh population shall be conducted by OMCs once in two years through

E(P)Act,1986 approved labs for the following parameters from the nearest source and report submitted to SPCB.

S.No.	Parameter	Permissible Limit
1	Total Petroleum hydrocarbons	600 µg/l
2	BTEX	i. Benzene- 950 µg/l ii. Toluene- 300 µg/l iii. Xylenes- a. o-xylene- 350 µg/l b. m & p–xylene- 200 µg/l
3	Ethanol	1400 µg/l
4	Methyl Tertiary Butyl Ether	13 µg/l
5	PAH	0.0001 µg/l

26. Enforcement agencies including SPCB can collect samples in and around petrol pump to check contamination.

NOTE:

i. Bihar State Pollution Control Board reserves the option to revise or add other conditions, if necessary, for protection of Environment in general and for Pollution Control in particular;

ii. The present NOC should not be construed as an assurance for the grant of 'Consent-to-Operate' the proposed plant but shall be subject to compliance of all the conditions indicated above;

iii. The NOC, for the Petrol Pump granted shall be valid for a period of twelve months from the date of issue.

01/11/2021

(S.N.Thakur)
Regional Officer, Purnea

Copy to:

M/s HSD Retail Outlet Dealership of IOCL,
Proprietor- Sri Ajay Kumar,
At+P.o-Hulash, Ps.-Raghopur,
Dist. – Supaul-852111.

(40)

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आंध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 22-10-2021

Agency Name.	AJAY KUMAR
Application No.	19949280934
MoEF/SG File No.	FP/BR/OTHERS/49280/2020
Location.	BIHAR
Address.	S/0Shri Manik Chand yadav, AT+PO-Hulash, PS-RaghopurSupaul
Amount(in Rs)	773156/-

Amount in Words :Seven Lakh Seventy-Three Thousand One Hundred and Fifty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	1506219949280934 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आंध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 22-10-2021

Agency Name.	AJAY KUMAR
Application No.	19949280934
MoEF/SG File No.	FP/BR/OTHERS/49280/2020
Location.	BIHAR
Address:	S/0Shri Manik Chand yadav, AT+PO-Hulash, PS-Raghopur Supaul
Amount(in Rs)	773156/-

Amount in Words :Seven Lakh Seventy-Three Thousand One Hundred and Fifty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	1506219949280934 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

ग्राहक की पावती

BKDHC 3129 5944 226 of Amt 773156 की रसीद स्वीकार करते हैं।

अनुदेश(एस) संदर्भ संख्या......

......अधिकारी का नाम तथा हस्ताक्षर......

बैंक स्टाम्प

प्राप्ति का दिनांक तथा समय के साथ

(41)

FORM-I

(For Triber Project)

Government of Bihar

Office of the Disstrict Collector Supaul

****

No......550...   Dated ...25/09/21

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter no. 11-9/98 EC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission to evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act. 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with M0EF's latter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, It is certified that .0285 Sq. Hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Indian Oil Corporation Limited (name of user agency) for Retail Outlet (proposed for diverson of forest land) in Supaul District falls within jurisdiction of Shripur village (s) in Pratapganj tehsils.

It is further certified that

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire .0285 Sq. hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of consultations and meeting of the forest rights committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level-Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 3

(b) The divesion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(c) The proposal doe's not involve recognised rights of Primitive tribal groups and preagricultural communities.

Encl. : As above

District Magistrate

Supaul

महेन्द्र कुमार, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी सुपौल के अध्यक्षता में (रैखिक परियोजना निर्माण हेतु) दिनांक 09.09.2021 को अनुमंडल पदाधिकारी वीरपुर /वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सुपौल एवं जिला कल्याण पदाधिकारी, सुपौल की संयुक्त बैठक में **(FRA 2006)** के तहत् विमर्श उपरांत लिये गये निर्णय के संबंध में:– 33

दिनांक 09.09.2021 को जिलाधिकारी सुपौल की अध्यक्षता में अनुमंडल पदाधिकरी, वीरपुर/वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल/ जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सुपौल एवं जिला कल्याण पदाधिकारी, सुपौल की संयुक्त बैठक में विमर्श उपरांत एवं अनुमंडल पदाधिकारी वीरपुर के पत्रांक 585 दिनांक 28.04.2021 के द्वारा प्रतिवेदन के आधार पर निर्णय लिया गया कि मौजा–श्रीपुर ,अंचल– प्रतापगंज में प्रयोक्ता एजेंसी मेसर्स इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट निर्माण के लिए एन0 एच0– 57 में पड़ने वाले पथ पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के .0285 Sq- हेक्टेयर रकवा के अपयोजन **(DIVERSION)** हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के आवेदन पर जॉचोपरान्त पाया गया कि प्रस्तावित योजना के लिए अपयोजित होने वाली भूमि जिसे राज्य सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग की अधिसूचना सं0 190E दिनांक 16.02.1994 से सुरक्षित वन **(PROTECTED FOREST)** घोषित किया गया है, परन्तु उस पर किसी तरह की अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी **(O T F D)** की आबादी नहीं है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी वीरपुर के पत्रांक 585 दिनांक 28.04.2021 के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं मानते हुए अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है।

ह0—
जिला पदाधिकारी,
सुपौल ।

ज्ञापांक 509 /दिनांक 09-09-2021

प्रतिलिपि :– सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/9/2021
जिला पदाधिकारी,
सुपौल ।

बिहार सरकार
कुमार सत्येन्द्र यादव, बि०प्र०से०
अनुमंडल पदाधिकारी, वीरपुर।

बिहार सरकार
अनुमंडल कार्यालय, वीरपुर
वीरपुर – 854340
(आपूर्ति शाखा)

दूरभाष : 06471–222035 (कार्या0)
06471–222035 (फैक्स)
06471–222034 (आवास)
06471–222034 (फैक्स)
Mobile : 9473191348
E-mail : sdo-birpur-bih@gov.in

पत्रांक 585-2 / आ0

प्रेषक,

अनुमंडल पदाधिकारी,
वीरपुर।

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
सुपौल।

वीरपुर, दिनांक 28/4 /2021

विषय :– सुपौल जिलान्तर्गत मौजा–श्रीपुर, अंचल–प्रतापगंज में रिटेल आउटलेट के परियोजना गाँव में अनुसूचित जन जाति के आबादी का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक 243–2, दिनांक 16.04.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहनाहै कि सुपौल जिलान्तर्गत मौजा–श्रीपुर, अंचल प्रतापगंज में रिटेल आउटलेट खोलने हेतु अनुसूचित जन जाति की आबादी एवं रेखांखित क्षेत्र में वन भूमि अपयोजन से संबंधित मामले में उक्त पंचायत में ग्राम सभा आयोजित कर निर्णय लिया गया है कि मौजा श्रीपुर, प्रखंड प्रतापगंज में अनुसूचित जन जाति की आबादी नहीं है तथा वे लोग इस मौजा से विस्थापित नहीं हुए है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रतापगंज ने अपने पत्रांक 194–2, दिनांक 26.02.2021 से प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के समीप अनुसूचित जन जाति की आबादी नहीं है एवं वन भूमि प्रभावित नहीं होता है।

ग्राम पंचायत श्रीपुर द्वारा ग्राम सभा में लिए गये निर्णय एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रतापगंज के प्रतिवेदन के आलोक में अपर प्रधान मुख्य सचिव (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी(वन संरक्षण), बिहार, पटना के पत्रांक 1144, दिनांक 08.11.2017 तथा अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के आलोक में अनुमंडलस्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त पंचायत में रिटेल आउटलेट खोलने में अनुसूचित जन जाति का अधिकार हनन नहीं होता है।

अतः वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु जिलाधिकारी, सुपौल को अनुशंसा करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन
28/04/21
अनुमंडल पदाधिकारी,
वीरपुर।

अनुलग्नक :–

1. ग्राम सभा की कार्यवाही की प्रति।
2. अनुमंडलस्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही की प्रति।

166
(31)

अनुमंडल कार्यालय, वीरपुर

कुमार सत्येन्द्र यादव, बि०प्र०से०, अनुमंडल पदाधिकारी, वीरपुर की अध्यक्षता में दिनांक 27.04.2021 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में आयोजित अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :–

सर्वप्रथम अनुमंडल पदाधिकारी, वीरपुर द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

प्रस्ताव संख्या :– 01

सर्वप्रथम ग्राम पंचायत श्रीपुर, प्रखंड प्रतापगंज की दिनांक 25.02.2021 को आयोजित ग्राम सभा की कार्यवाही की प्रति पटल पर रखा गया। ग्राम सभा द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त पंचायत में अनुसूचित जन जाति की आबादी नहीं है तथा इस गाँव से आदिवासी विस्थापित नहीं हुए है।

प्रस्ताव संख्या :– 02

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सुपौल के ज्ञापांक 243–2, दिनांक 16.04.2021 के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक 574–2/आ0, वीरपुर, दिनांक 24.04.2021 द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) –सह– नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना के पत्रांक 1144, दिनांक 08.11.2017 तथा अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा संशोधित की जानकारी सभी सदस्यों को दी गई।

प्रस्ताव संख्या :– 03

सुपौल जिलान्तर्गत मौजा श्रीपुर, प्रखंड प्रतापगंज में रिटेल आउटलेट खोलने के संदर्भ में अनुसूचित जन जाति से संबंधित अपयोजित होने वाले वन भूमि के संबंध में विचार विमर्श किया गया।

प्रस्ताव संख्या :– 04

ग्राम पंचायत श्रीपुर, प्रखंड प्रतापगंज के ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि उक्त पंचायत में अनुसूचित जन जाति की आबादी नहीं है। अनुमंडल वनाधिकार समिति द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त पंचायत में रिटेल आउटलेट खोलने में अनुसूचित जन जाति का अधिकार का हनन नहीं होता है।

अतः वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफ0आर0ए0) के तहत प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु जिलाधिकारी, सुपौल को अनुशंसा करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(हस्ताक्षर) 27/4/21

अनुमंडल पदाधिकारी,
वीरपुर।

165

(38)

ज्ञापांक 584-2/आ0, वीरपुर, दिनांक 27.04.2021

प्रतिलिपि :– सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वन क्षेत्र पदाधिकारी, वीरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, वीरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, सुपौल की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

27/4/21

अनुमंडल पदाधिकारी,
वीरपुर।

बिहार सरकार
GOVERNMENT OF BIHAR
प्रखंड विकास पदाधिकारी,
प्रतापगंज।

बिहार सरकार
प्रखंड कार्यालय, प्रतापगंज
प्रतापगंजः– 852125

दूरभाषः– 06471287134
मो0 नं0:– 9431818616
फैक्स :– 06471287134
ई–मेलः–bdo.pra-su-bih@nic.in
Website :www.eblocks.bih.nic.in

पत्रांक 194-2 दिनांक 26/02/2021

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी,
बीरपुर।

विषयः– सुपौल जिला अंतर्गत मौजा श्रीपुर अंचल प्रतापगंज में रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु अनुसूचित जनजाति के आबादी के संबंध में।

प्रसंगः– भवदीय पत्रांक 273–2/ आ0 दिनांक 03/02/2021 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय प्रासांगिक पत्र की जाँच संबंधित पंचायत के सचिव एवं मुखिया से संयुक्त रूप से करायी गई । जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वर्तमान में ग्राम पंचायत श्रीपुर में अनुसूचित जनजाति की संख्या शून्य है। जाँच प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जाता है।

अनुरोध है कि पावती स्वीकार की जाय।

अनुलग्नकः–
यथोक्त।

विश्वासभाजन
26/2/2021
प्रखंड विकास पदाधिकारी,
प्रतापगंज।

कार्यालय ग्राम पंचायत श्रीपुर

ज्ञापांक:– 04 / दिनांक:– 26 / 2 / 2021.

प्रेषक:– मुखिया ग्राम पंचायत श्रीपुर।

प्रेषित:–

सेवा में

श्रीमान, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय,प्रतापगंज।

विषय:– भवदीय ज्ञापांक:– 183–2, दिनांक:–24.02.2021 से संबंधित जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में सुचित करना है कि ग्राम पंचायत श्रीपुर में 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसुचित जनजाति के बीस जनसंख्या बताया गया है जबकि ग्राम पंचायत श्रीपुर में एक भी अनुसुचित जनजाति की आबादी वर्तमान में नहीं है, पूर्व में भी श्रीमान को इसकी जाँच प्रतिवेदन मुखिया एवं पंचायत सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से दी गई है। ग्राम पंचायत श्रीपुर के कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाकर माननीय मुखिया श्रीमति सत्यभामा देवी की अध्यक्षता में की गई तथा सर्वसम्मति से ध्वनिमत से पारित किया गया कि अनुसुचित जनजाति की आबादी वर्तमान में नहीं है।

अतः श्रीमान को सादर सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

अनुलग्नक:– कार्यकारिणी समिति की सत्यापित छायाप्रति।

पंचायत सचिव

सत्यभामा देवी
मुखिया
ग्राम पंचायत श्रीपुर

आज दिनांक 25-02-2021 को दिन के 11 बजे माननीय मुखिया श्रीमति सत्यभामा देवी की अध्यक्षता में स्थानीय पंचायत भवन श्रीपुर में कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाई गई।

बैठक का मुख्य विषय 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के आबादी एवं अन्यान्य विषय पर विचार

पंचायत सचिव (25-2-21) — सत्यभामादेवी
मुखिया सह
अध्यक्ष ग्राम पंचायत
श्रीपुर

(1) पप्पू कुमार मेहता वार्ड - 07
[illegible] वार्ड - 13
[illegible] कुमार वार्ड - [illegible]
[illegible] देवी वार्ड नं० 12
मुन्नी देवी वार्ड [illegible]
कुमकुम झा वार्ड नं० [illegible]
(7) सरिता देवी वार्ड नं०-2
(8) नागेश्वर ठाकुर वार्ड नं०-04
(9) सुरेन्द्र झा उपमुखिया वार्ड नं०-03
[illegible] वार्ड - 6

प्रस्ताव संख्या 01 :-

गत बैठक की सम्पुष्टि की गई।

(23)

61 (20)

प्रस्ताव संख्या 02:-

माननीय मुखिया सह अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सदस्यों को बताया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी [illegible] प्रतापगंज के ज्ञापांक 182 [illegible] 2021 के आदेशानुसार एक [illegible] गया है कि ग्राम पंचायत [illegible] के जनगणना के अनुसा[illegible] जनजाति की जनसंख्या [illegible] है बताई [illegible] श्रीपुर [illegible] तक एक भी [illegible] जनजाति का नहीं है।

प्रस्ताव संख्या 03:-

बैठक में [illegible] श्री चंदेश्वर यादव द्वारा [illegible] गया कि [illegible] उम्र 65 साल हो गई है [illegible] इसी पंचायत में हुआ है [illegible] तक हमने श्रीपुर ~~[illegible]~~ पंचायत में एक भी अनुसूचित जनजाति को [illegible] देखा है। उपस्थित सभी सदस्यों ने ध्वनि मत से इसकी स्वीकृति दी है।

प्रस्ताव संख्या 04:- धन्यवाद ज्ञापनोपरांत बैठक की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

[illegible] 25-2-21 पंचायत सचिव

सत्यभामादेवी मुखिया सह अध्यक्ष श्रीपुर